

**Assocham asks parties
to aim for 8.5% growth**

NEW DELHI

Industry body Assocham released a charter of demands to make India a \$5 trillion economy by 2025 and called on political parties to incorporate the same in their Lok Sabha poll manifestos. Parties should take a pledge, among other steps, to enable a growth rate of 8-8.5% per annum. Some of the demands include simplification of GST structure and time-bound dilution of government's stakes in PSUs. PTI

Assocham releases charter of demands for political parties; pitches for 8-8.5% growth rate

PTI ■ NEW DELHI

Industry body Assocham Sunday released a charter of demands to make India a \$5 trillion economy by 2025 and called on political parties to incorporate the same in their Lok Sabha poll manifestos.

Listing out the charter, Assocham in a statement said it wants political parties to pledge, among other steps, to enable growth rate of 8-8.5 per cent per annum.

Some of demands that Assocham wants political parties to incorporate in their 2019 election manifestoes include simplification of GST structure, time bound dilution of government stake in Public Sector Undertaking (PSUs), providing tax rebate of 1 per cent to companies that offer over 20 per cent jobs for women and cut in corporate income tax for MSME sector.

It further suggested expeditious roll-out of Ayushman Bharat and reducing education cost by minimising GST on outsourced education services from 18 per cent to 5 per cent.

To boost economic growth and investment, the industry body has suggested creation of development finance institutions to provide long term non-bank funding option to the



industry.

To improve farmers' income, the industry body suggested the exemption of GST on leasing services for farm equipment and machinery, as well as creation of Technology Up-gradation Fund (TUF) for agriculture to provide capital subsidy.

"Alleviate the losses to farmers from perishable produce by setting up robust supply chain system and cold storage or equivalent facilities at airports/ stock junctions for efficient transportation," it said.

To boost manufacturing, the industry has pitched for gradual simplification of GST structure aiming for dual rate slab 8 and 16 per cent.

It has also suggested reduction in the corporate income tax to 15 per cent (from present 25 per cent) for the Micro, Small and Medium Enterprises

(MSME) over a period of 5 years and 20 per cent (from present 30 per cent) for large companies over a period of 5 years.

Among other steps, the industry body has suggested taxing income from renting of housing properties at a flat rate of 10 per cent, deduction from rental income under Section 24(a) to be increased from 30 per cent to 50 per cent to improve Rate of Return from renting.

It suggested exemption of long term capital gain on securities held for 3 years and more and an additional 50 lakh limit be given under Section 54EC for investment in CPSE ETFs bond market.

The Lok Sabha polls will be held in seven phases starting April 11. All political parties are in the process of preparing their election manifesto.

उद्योग मंडल एसोचैम ने रखी चुनावी मांगें

■ नई दिल्ली (भाषा)।

उद्योग मंडल एसोचैम ने आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों के लिए रविवार को अपनी मांगों की एक सूची जारी की जिसमें देश को 2025 तक पांच हजार अरब रुपए की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इन दलों से अपने चुनावी घोषणा पत्र को तैयार करते समय इन मांगों पर गौर करने का अनुरोध किया गया है।

एसोचैम ने एक बयान में कहा कि सभी राजनीतिक दल इस बात की शपथ लें कि वह देश की सालाना आर्थिक वृद्धि दर को 8 से 8.5 फीसद रखने के लिए कदम उठाएंगे।

एसोचैम ने जीएसटी के सरलीकरण की मांग की है और सभी राजनीतिक दलों से इसे उनके चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा बनाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा लोक

■ चुनावी घोषणा पत्र में आर्थिक वृद्धि दर में तेजी लाने के उपाय किए जाएं शामिल
■ महिलाओं को जॉब देने वाली कंपनियों को मिले प्रोत्साहन

उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी का समय से विनिवेश, महिलाओं को 20 फीसद से अधिक नौकरियां देने वाली कंपनियों को कर में एक फीसद की छूट और एमएसएमई उद्योग क्षेत्र को कारपोरेट आयकर में कटौती

इत्यादि मांगे भी एसोचैम ने रखी हैं। साथ ही बाहर से ली जाने वाली शैक्षिक सेवाओं पर जीएसटी को 18 फीसद से घटाकर पांच फीसद करने और आयुष्मान भारत को तेजी से लागू करने की भी मांग एसोचैम ने रखी है।

एसोचेम ने राजनीतिक दलों के सामने रखी चुनावी मांगों

नई दिल्ली, भाषा। उद्योग मंडल एसोचेम ने आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दलों के लिए रविवार को अपनी मांगों की एक सूची जारी की जिसमें देश को 2025 तक पांच हजार अरब रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए इन दलों से अपने चुनावी घोषणा पत्र को तैयार करते समय इन मांगों पर गैर करने का अनुरोध किया गया है। एसोचेम ने एक बयान में कहा कि सभी राजनीतिक दल इस बात की शपथ लें कि वह देश की सालाना आर्थिक वृद्धि दर को 8 से 8.5 प्रतिशत रखने के लिए कदम उठाएंगे। एसोचेम ने जीएसटी के सरलीकरण की मांग की है और सभी राजनीतिक दलों से इसे उनके चुनावी घोषणापत्र का हिस्सा बनाने का अनुरोध किया है। इसके अलावा लोक उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी का समय से विनिवेश, महिलाओं को 20 प्रतिशत से अधिक नोकरियां देने वाली कंपनियों को कर में एक प्रतिशत की छूट और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम (एमएसएमई) उद्योग क्षेत्र को कारपोरेट आयकर में कटौती इत्यादि मांगें भी एसोचेम ने रखी हैं। साथ ही बाहर से ली जाने वाली शैक्षिक सेवाओं पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत करने और आयुष्मान भारत को तेजी से लागू करने की भी मांग एसोचेम ने रखी है।